



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 13, 2016/आश्विन 21, 1938

No. 326]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 2016/ASVINA 21, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2016

**विषय :** चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर, उत्पाद चाकू और प्रसाधन मर्दों को छोड़कर, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच

सं. 14/05/2016-डीजीएडी.—ऑल इंडिया पोटर्री मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (एआईएमपीए) और इंडियन सेरामिक सोसाइटी (जिसे आगे याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ता एसोसिएशन कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की

शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

### घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

3. यह याचिका भारत में पीयूसी के घरेलू उत्पादकों की ओर से ऑल इंडिया पोटर्री मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (एआईएमपीए) और इंडियन सेरामिक सोसाइटी (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता/ याचिकाकर्ता एसोसिएशन कहा गया है) द्वारा दायर की गई है। कुछ भारतीय उत्पादकों अर्थात् (क) क्ले क्राफ्ट(आई) प्रा. लि., (ख) सेरामिक टेबलवेयर प्रा. लि., (ग) भारत पोटर्रीज लि. और (घ) मै. यूपी सेरामिक्स एंड पोटर्रीज प्रा. लि. (जिन्हें याचिकाकर्ता/ याचिकाकर्ता एसोसिएशन कहा गया है) ने आवश्यक लागत और वित्तीय सूचना प्रदान की है। अनेक उत्पादकों का यशवी एंटरप्राइजेज, अनिल सेरामिक, सम्राट सेरामिक्स, रघुवीर (इंडिया) लिमिटेड, मारवेल सेरामिक्स प्रा. लि., शी सेल सेरामिक्स (इंडिया) प्रा.लि., मुद्रिका सेरामिक्स (आई) लि., शान टेबलवेयर प्रा. लि., फेदर टच सेरामिक्स प्रा. लि., ओसिस सेरामिक्स प्रा. लि. और टाटा सेरामिक्स लि. ने याचिका का समर्थन किया है। इन उत्पादकों ने उनके समर्थन पत्रों में भार के अनुसार उनकी उत्पादन और बिक्री मात्राओं का ब्योरा उपलब्ध कराया है।
4. सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआईआर) के अनुसार कुल भारतीय उत्पादन को दर्शाने वाला एक विवरण दर्शाया गया है कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में उत्पादन के अनेक उत्पादक हैं।
5. इसके अलावा, याचिकाकर्ता कंपनियों ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध देश से न तो विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित हैं।
6. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन समान वस्तु के सकल घरेलू उत्पादन में 'प्रमुख हिस्सा' बनता है। अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

### विचाराधीन उत्पाद

7. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद चाकू और प्रसाधन मदों को छोड़कर सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है)।
8. याचिकाकर्ताओं ने आगे स्पष्ट किया है कि बोन चाइना, स्टोनवेयर और पोर्सलेन-वेयर सभी सेरामिक उत्पाद हैं और इसलिए विचाराधीन उत्पाद में बोन चाइना, स्टोन और पोर्सलेन के किचन वेयर और टेबलवेयर शामिल हैं। सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर उत्पाद का प्रयोग खाना खाने, पानी पीने और खाना और पेयों को परोसने में किया जाता है और घरों और होटलों में सजावट के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पीयूसी विभिन्न आकृति और आकार में उपलब्ध है और यह जांच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न विश्लेषण के लिए वजन मामले में माप की इकाई लेने का फैसला किया गया है।
9. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 69 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। संबद्ध वस्तु के आयात एचएस कोडों 6911 और 6912 के अधीन विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत हो रहे।

किसी भी प्रकार से सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जॉच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

### समान वस्तु

10. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद सामान्य और भौतिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशन, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है (और कर रहे हैं)।
11. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी वर्तमान जॉच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' मानते हैं।

### शामिल देश

12. वर्तमान जॉच चीन (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन से संबंधित है।

### सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन के संबंध में नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने भारत में उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करके चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य का दावा किया है। नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 के अनुसार यह माना जाता है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अधीन कार्य कर रहे हैं।
14. उक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता और चीन जन. गण. में प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन. गण. के लिए संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है।

### निर्यात कीमत

15. याचिकाकर्ताओं ने भारत में संबद्ध आयातों की मात्रा और मूल्य का आकलन करने के लिए डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सौदा-वार आयात आकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़े, बैंक प्रभार और वैट के लिए समायोजनों में कीमत संबंधी समायोजनों का दावा किया गया है।

### पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से अधिक है, जिससे यह पता चलता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का

पाटन किया जा रहा है। इस प्रकार अनुमानित पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है।

### **क्षति और कारणात्मक संबंध**

17. यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

### **जांच अवधि (पीओआई)**

18. याचिकाकर्ताओं ने 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 (12 महीनों) की जांच अवधि का प्रस्ताव किया है। तथापि क्षति के विश्लेषण के लिए पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल 12 – मार्च 13, अप्रैल 13 – मार्च 14, अप्रैल, 14 – मार्च, 15 और जांच की प्रस्तावित अवधि के आकड़ों पर विचार किया गया है।

### **सूचना प्रस्तुत करना**

19. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**  
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग**  
**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,**  
**नई दिल्ली- 110001**

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

### **समय-सीमा**

21. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने

उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

#### **अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

23. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में " गोपनीयता " का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय " या "अगोपनीय " अंकित होना चाहिए।
24. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पाँच (5) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
25. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।
26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है ,पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध /रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि , आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
27. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
28. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

29. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

#### **असहयोग**

30. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th October, 2016

**Subject: Anti-Dumping investigation concerning imports of Ceramic Tablewares and Kitchenwares, excluding knives and toilet items, originating in or exported from China PR**

**No. 14/05/2016-DGAD:** All India Pottery Manufacturers' Association (AIPMA) and the Indian Ceramic Society (herein referred as petitioners/ petitioner associations) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of Ceramic tableware and kitchenware, originating in or exported from China.

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

**Domestic Industry & Standing**

3. The petition has been filed by All India Pottery Manufacturers' Association (AIPMA) and the Indian Ceramic Society (herein referred as petitioners/ petitioner associations) on behalf of domestic producers of the PUC in India. Some of the Indian Producers i.e. (a) Clay Craft (I) Pvt. Limited, (b) Ceramic Tableware Pvt. Ltd., (c) Bharat Potteries Ltd. and (d) M/s. UP Ceramics & Potteries Pvt. Ltd. (referred as petitioners/ petitioner companies) have provided the necessary costing and financial information. The petition has been supported by a number of other producers, namely, Yashvi Enterprise, Anil Ceramic, Samrat Ceramics, Raghuvir (India) Limited, Marvel Ceramics Private Limited, Sea Shell Ceramics (India) Private Limited, Mudrika Ceramics (I) Ltd., Shan Tablewares Private Limited, Feather Touch Ceramics Private Limited, Oasis Ceramics Private Limited and Tata Ceramics Limited..

4. The total Indian production has been estimated on the basis of data given by Central Glass & Ceramic Research Institute (CSIR). They have mentioned details of producers of the product in the organized sector as well as in the unorganized sector.

5. Further, the petitioner companies have certified that they have neither imported the product under consideration from subject country, nor are they related to any exporter of the product under consideration in subject country or to an importer in India.

6. As per the evidence available on record, the production of the petitioner companies accounts for a major proportion in the gross domestic production of the like article. The Authority, therefore, determines that the petitioner constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

**Product under consideration**

7. The product under consideration in the present petition is defined as "Ceramic tablewares and kitchenwares, excluding knives and toilet items" (hereinafter referred to as 'subject goods').

8. The petitioners have further clarified that bone china, stoneware and porcelain-ware all constitute ceramic products and therefore the product under consideration includes kitchenware and tableware of bone china, stone and porcelain. Ceramic tableware and kitchenware products are used for the purpose of eating, drinking and serving food and beverages and for decoration in homes and hotels. The PUC is available in various shape and sizes and it has been decided to take the unit of measurement in weight terms for various analyses during the process of investigation.

9. Product under consideration is classified under Chapter 69 of the Customs Tariff Act, imports are taking place under various sub headings under HS code 6911 and 6912. Customs classification is inanycase, indicative and not binding on the scope of the product under consideration in the present investigation.

**Like Article**

10. Petitioners have claimed that the goods produced by the domestic industry and the products imported from the subject country are like article. Product under consideration produced by the domestic industry in general and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical characteristics, product specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used (and are using) the two interchangeably.

11. The applicant has further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicant in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

**Country/(ies) involved**

12. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China (referred to as the subject country).

**Normal Value**

13. Applicant has claimed that China should be treated as a non-market economy and normal value in case of China should be determined in accordance with para-7 and 8 of Annexure I of the Rules. The applicant has claimed normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted. In terms of Para 8 in Annexure I to the Rules it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non market economy conditions.

14. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from China PR, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules.

**Export Price**

15. Petitioners have determined export price on the basis of transaction wise import data procured from DGCI&S to assess the volume and value of subject imports in India. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight, bank charges, and adjustment for VAT to arrive at the net export price.

**Dumping Margin**

16. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country are higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margin is estimated to be above de minimis.

**Injury and Causal Link**

17. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price suppression, price underselling and consequent significant adverse impact in terms of profits, return on capital employed, and cash flow to the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

**Period of Investigation (POI)**

18. Petitioners proposed the period of investigation from 1<sup>st</sup> April 2015 to 31<sup>st</sup> March 2016 (12 months). However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e. April 2012-March 2013, April 2013-March 2014, April 2014-March 2015 and the proposed period of investigation has been considered.

**Submission of information**

19. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,  
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce  
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,  
New Delhi -110001.**

20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

**Time limit**

21. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

22. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

**Submission of Information on Non-Confidential basis**

23. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

24. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

25. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.



**Inspection of Public File**

29. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

30. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority